an>

Title: Regarding Indira Awas Yojana.

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, इंदिरा आवास योजना ग्रामीण विकास विभाग की एक बहुत ही बड़ी योजना है। लेकिन प्रशासनिक अमले की निष्क्रियता के कारण यह योजना दम तोड़ रही है। आवंटित आवासों में नाम किसी का है और रहता कोई और है। प्रतीक्षा सूचियों में किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन इंदिरा आवास किसी दूसरे को आवंटित कर दिया गया है। अभी हाल ही में, सीएजी की रिपोर्ट में वर्ष 2012-2013 में कहा गया कि इंदिरा आवास योजना के लिए झारखण्ड सरकार, केन्द्र सरकार से 256.42 करोड़ रुपए नहीं ले सकी। साथ ही अतिरिक्त बोझ के डर से 9.90 लाख बीपीएल परिवारों को इस योजना का लाभ नहीं दिया गया है। जांच में चौदह प्रखण्डों में पाया गया कि 25.425 लाभांवितों का चयन ग्राम सभा के बिना हुआ। सबसे महत्वपूर्ण खुलासा यह हुआ कि 593 ऐसे लोगों को इंदिरा आवास स्वीकृत किये गये, जिनके नाम बीपीएल सूची में नहीं हैं। गरीब लेग भूमि वितरण के अभाव में इस योजना से बाहर हो जाते हैं तथा हमेशा के लिए इस योजना के लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि ग्रामीण भारत की इस महत्वाकांक्षी योजना को विफल होने से बचाया जाए तथा इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच कराएं। धन्यवाद।